यह है कि दो डिब्बों के दरम्यान जो स्पेस होती है, उससे भी लोग सफर करते हैं और कितने खतरनाक हालात से यह गुजरते हैं, इसका आपको अंदाजा होना चाहिए।

पिछले दिनों एक दिन में 300 ऐसे रिफ्यूजी हिन्दुस्तान आये और उसके साथ जो अटारी पर मृतक होता है (समय की घंटी) चाहे वह कस्टम अफसर हिन्दुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, यह इन्तहाई शर्म की बात है कि जो हमारे भाई इतने दिनों से वहां आजाद थे, जब वह मुसीबत के दिनों में आज हिन्दुस्तान आ रहे हैं, तो लोगों बजाय उनकी मदद करने के हमारे कस्टम के अधिकारी और पोर्टज उनकी जेब और काटते हैं और उनसे छीना झपटी करते हैं। मैं आपकी अदालत से आपके माध्यम से हिन्दुस्तान की सरकार से यह दर्खास्त करना चाहता हूं कि सबसे पहले अफगानिस्तान की गर्वनमेंट से इस मामले को उठाना चाहिए कि वे लोग हिन्दुस्तानी ओरिजन के हैं, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो लोग वहां से आना चाहते हैं उनको बाहिफाजत लाने का इन्तजाम करना चाहिए। तीसरे वह यह जो हिन्दुस्तान आ गये हैं उनकी भी रिडेक्शन का उनके खाने पीने का और उनकी हिफाजत का इन्तजाम हिन्दुस्तान की गर्वनमेंट को करना चाहिए। यह बहुत सीरियस मामला है। मैं उम्मीद करता हूं भारत सरकार से कि वह इसकी तरफ पूरी तब्बजह देगी।

Non-filling up of Vacancies against SC/ST Quota by Delhi Administration

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): मैडम, संविधान के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन दिल्ली प्रशासन द्वारा इन लोगों को जो अधिकार दिया हुआ है उसकी उपेक्षा की जा रही है। दिल्ली प्रशासन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो बैकलाग है वह काफी दिनों से चला आ रहा है। प्रशासन की ओर से उसको पूरा करने में अपनी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप इन लोगों के जो अधिकार हैं, उनको पूरा करने के लिए, उस बैकलाग को पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन को निर्देश दें कि जो पिछड़े हुए हैं, जो समाज में नीचे गिरे हुए हैं, उनको जो अधिकार दिए हैं, उनको यदि समाज के बराबर लाना है तो उस अधिकार का उपयोग व प्रयोग होना चाहिए जिससे कि वे समाज में बराबर आ सके। मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन के पुलिस विभाग के अंदर कई रिक्तियां हैं। शिक्षा विभाग के अंदर तीन साल से अब तक कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है जबकि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कोटा है हजारों रिक्त पद खाली है। यहां तक कि एम०डी०एम०सी० के अंदर इन लोगों के लिए जो स्थान रिक्त थे उन स्थानों पर सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही यातायात विभाग के अंदर भी यही हाल है चाहे दिल्ली प्रशासन को लें तो दिल्ली प्रशासन के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो रिक्तियां हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों की जो पदोन्नति जारी की जा रही है। मैं सरकार से यह चाहता हूं ...**(व्यवधान)**।

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Madam, I am on a point of order. Mr. Yashwant Sinha and I went to the Vijay Chowk. The police did not allow us to walk across the Vijay Chowk. We said, "You can frisk us, we are M.Ps." He asked us ... *(interruption)* ...

श्री मूलचन्द मीणा: मोरारका जी। यह आपने बीच में क्या शुरू कर दिया। ...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): One minute, Mr. Meena. Let him speak. I have permitted him to speak. I will call you again. Please speak, Mr. Morarka.

SHRI KAMAL MORARKA: Madam, the police did not allow us to go ... *Interruptions)* ...

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण (पंजाब): जब एक आदमी बोल रहा है तो उसको अपनी बात बोलने दीजिए आप इनकी बात क्यों नहीं सुनते? यह बड़ा सीरियस मामला है, शेड्यूल्ड कास्ट्स का मामला है। इसको सुनना चाहते हैं।